विवादों पर अड़ियल रुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूर किसी भी केंद्रीय मंत्री, बड़े नेता या प्रमुख राजनीतिक दल ने चीन को बधाई देने की जरूरत महसूस नहीं की। चीन की पूरी कोशिश है कि नए दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह उसके नियंत्रण में रहे।

सुंदर सिंह।

बीते एक सप्ताह में भारत ने चीन को जो तीन बेहद कड़े संदेश दिए हैं, उनकी अहमियत कूटनीतिक जगत में छुपी नहीं रह सकती। इस महीने की एक तारीख को जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी स्थापना के सौ साल पूरे करने के मौके को धूमधाम से सेलिब्रेट कर रही थी, पड़ोसी देश भारत ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूर किसी भी केंद्रीय मंत्री, बड़े नेता या प्रमुख राजनीतिक दल ने चीन को बधाई देने की जरूरत महसूस नहीं की। इस सांकेतिक चुप्पी को जो लोग संयोग मानकर चल रहे थे, उनके लिए दूसरा गहरा संदेश इसके तीन दिन बाद आया जब 4 जुलाई को अमेरिकी स्वाधीनता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडन को बाकायदा ट्वीट करते हुए बधाई दी। इसके भी तीन दिन बाद 7 जुलाई को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 86वें जन्मदिन के मौके पर न केवल प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सार्वजनिक तौर पर बधाई दी, बल्कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्कम जैसे चीनी सीमा से सटे राज्यों समेत सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई केंद्रीय मंत्रियों ने बधाई संदेशों के जरिए उनका अभिनंदन किया। यह पहला मौका है जब मोदी ने दलाई लामा को सार्वजनिक तौर पर जन्मदिन की बधाई दी है।

ट्यूनिशिया में पहली महिला के प्रधानमंत्री बनने से दुनिया हैरान, अरब देशों में कैसे हैं महिलाओं के हालात? साल 2015 में दलाई लामा ने मोदी को जन्मदिन की बधाई दी थी, जिस पर उन्होंने उनके प्रति आभार जताया था। मगर इसके बाद चीन की इस मामले में अतिरिक्त संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने थोड़ी सावधानी बरतना ठीक समझा। साल 2018 में दोनों पक्षों में यह सहमति भी बनी थी कि दोनों देश एक–दूसरे की संवेदनाओं, हितों और चिंताओं का सम्मान करेंगे और आपसी असहमतियां सार्वजनिक रूप से नहीं दर्शाएंगे। लेकिन चीन ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े विवादों पर और चीन–पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर, जम्मू कश्मीर के स्टेटस आदि मसलों पर भारतीय संवेदनाओं, हितों और चिंताओं के प्रति जिस तरह का रवैया दिखाया, उसके बाद भारत का अपने रुख पर पुनर्विचार करना जरूरी हो गया था। ध्यान रहे कि भारत के इस बदले रुख की अहमियत इस बात में भी है कि यह ऐसे समय सामने आया है, जब दलाई लामा के उत्तराधिकारी की तलाश का मुद्दा गरमा रहा है।

चीन की पूरी कोशिश है कि नए दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह उसके नियंत्रण में रहे। दूसरी ओर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि दलाई लामा का चयन तिब्बतियों का मामला है और यह काम पूरी तरह से उन्हीं पर छोड़ा जाना चाहिए। भारत ने अब तक इस मामले में अपना रुख साफ नहीं किया था। उसके ताजा संकेतों ने दुनिया भर में फैले तिब्बती समुदाय के बीच खुशी की लहर तो दौड़ाई ही है, यह भी साफ किया है कि सीमा पर दुश्मनीपूर्ण संबंध और आपसी विवादों पर अड़ियल रुख चीन के लिए भी कई स्तरों पर नुकसानदेह हो सकता है।

परीक्षा

अशोक वोहरा।

मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी भी क्यों पिला दी ?

किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा – अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दालान में दोनों अतिथि अलग–अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा – तुमने सुना नारद! किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला फिर भी वह मेरे गुण गए रहे है। यह तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो कई–कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है।

अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था – गोविन्द हरि–हरि। तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस, मुझे कुछ और नहीं चाहिए।

फिर दोनों अतिथियों से बोला – हरि की बड़ी कृपा है।

संपादकीय

सेना की मुस्तैदी

हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जमीन से संचालित होने वाले और वहां से समर्थन प्राप्त इस्लामिक आतंकवादी संगठन ही भारत के लिए प्रमुख खतरा हैं। पिछले दो दशकों में वे भी अपना असर खो चुके हैं। इसके पीछे इस्लामाबाद पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने समेत कई दूसरे कारण हैं। एक उड़ता हुआ अनुमान लगाया जा रहा है कि अफगानिस्तान में जेहाद की लड़ाई लड़ रहे आतंकी अब खाली हो चुके हैं। अफगान जीत के बाद इनका रुख जम्मू–कश्मीर की ओर हो सकता है।

जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद इस वजह से कम नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में लोग नहीं थे या उसके पास संसाधनों की कमी हो गई थी। आतंकी घटनाओं में गिरावट की वजह रही भारतीय सेना और स्थानीय स्तर पर उसे मिला समर्थन। दाएश ने जून 2014 में अपना नक्शा जारी किया था। यह नक्शा दिखाता था कि इस आतंकी संगठन का दुनिया में प्रभुत्व कहां है। इसमें भारत को 'विलायत खुरासान' के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। इससे इस आशंका को बल मिला कि बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमले हो सकते हैं। तब से सात बरस बीत चुके हैं। दाएश या उसके सहयोगी संगठनों ने कोई बड़ी वारदात नहीं की। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद इस आशंका को सिरे से खारिज कर देना नासमझी होगी कि आतंकी घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसी तरह घबराकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना भी नासमझी होगी।

अमेरिका की नीतियों को लेकर निश्चित तौर पर चिंताएं हैं, लेकिन सचाई यही है कि लंबे समय तक वह ऐसी शक्ति बना रहेगा, जो दुनिया को प्रभावित कर सके।

दाएश का असर घटा

अजय साहनी।।

अमेरिका पर 11 सितंबर को हुए आतंकी हमले को 20 बरस बीत चुके हैं। अगर पीछे मुड़कर देखें, तो इन दो दशकों में इस एक घटना की वजह से दुनिया पूरी तरह बदल गई। यह भी कम नाटकीय नहीं कि जब इस आतंकी वारदात की 20वीं बरसी करीब आ रही थी, तब अमेरिका तैयारी कर रहा था अफगानिस्तान से निकलने की। आखिर में उसकी वापसी पूरी तरह अराजक और लगाए गए अनुमानों के विपरीत साबित हुई। शायद यही कहना सही होगा कि तालिबान के सामने अफगानिस्तान को परोस दिया गया।

अफगानिस्तान से अमेरिका के यूं हटने को 1975 में साइगॉन में लड़ी गई अंतिम लड़ाई की तरह देखा जा रहा है। हालांकि उस घटना के बाद अमेरिका ने एक ग्लोबल सुपरपावर के रूप में खुद को काफी मजबूत किया। इस समय भी भले अमेरिकी शक्ति पर सवाल खड़े किए जा रहे हों, लेकिन उसकी ताकत बरकरार है। अब भी उसके पास ग्लोबल जीडीपी का 23 फीसदी हिस्सा है और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद चीन से लगभग छह गुना। अमेरिका की नीतियों को लेकर निश्चित तौर पर चिंताएं हैं, लेकिन सचाई यही है कि लंबे समय तक वह ऐसी शक्ति बना रहेगा, जो दुनिया को प्रभावित कर सके।

अमेरिका ने आतंकवाद विरोधी लड़ाई के नाम पर जो युद्ध छेड़ा, उसने पूरे मध्य पूर्व में अराजकता फैला दी। पश्चिमी देश चल पड़े इराक, सीरिया और लीबिया में, जिसे किसी तरह तार्किक नहीं कहा जा सकता। इसका नतीजा यह हुआ कि अफगानिस्तान में जहां अमेरिका के घुसने की एक वाजिब वजह थी, वहां उसकी ताकत कमजोर पड़ गई। इस सबका सबसे बुरा असर हुआ आतंकवाद के उभार के रूप में। थोड़े वक्त के लिए इस्लामिक स्टेट या दाएश उभरकर आ गया, जिसने बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ाया। 2014 में वैश्विक आतंकवाद चरम पर था। इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय था दाएश, लेकिन उसके बाद से इस संगठन का असर कम होता गया है। अंदेशा जताया गया था कि 2017 में दाएश के पतन के बाद घर लौटने वाले हजारों लड़ाके पश्चिम में हिंसा का दौर ला देंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन अनुमानों के बावजूद अमेरिका या यूरोप में कोई संगठित आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। अब पश्चिम में प्रमुख खतरा है घरेलू दक्षिणपंथी आतंकवाद। दुनिया में चल रही इन घटनाओं से भारत भी प्रभावित हुआ। 2001 में जब अमेरिका पर हमला हुआ था, वह साल आतंकवाद के लिहाज से भारत के लिए भी सबसे बुरा साबित हुआ। उस बरस 5504 लोगों की आतंकवादी घटनाओं में मौत हुई। केवल जम्मू–कश्मीर में ही 4011 जानें गईं। 2011 के बाद देशभर में होने वाली मौतों में कमी आई है। 2020 में यह संख्या घटकर 591 रह गई थी और इस साल पांच सितंबर तक आंकड़ा 366 है। जम्मू–कश्मीर में 2012 में सबसे कम जानें गईं, केवल 121। हालांकि बाद में इनकी संख्या बढ़ी। इस साल 5 सितंबर तक 162 लोग आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में जान गंवा चुके हैं। इन मामलों के बढ़ने की वजह है ध्रुवीकरण की राजनीति और संदिग्ध घरेलू नीतियां।

ओसामा बिन लादेन ने 1996 में अल कायदा की ओर से भारत में जिहाद का आह्वान किया था। इसके बाद कई बार इसी तरह की अपील की गई। साल 2014 में इस क्षेत्र के लिए अल कायदा ने एक संगठन खड़ा किया। जम्मू–कश्मीर में कुछ सफलता के बावजूद अंसार गजवत–उल–हिंद कोई प्रभावी नेटवर्क बनाने में विफल रहा। यह भारतीय जमीन पर कोई बड़ी वारदात नहीं कर सका है।

अष्टयोग-5021

3		1	4	7		
6	35	5	30		25	
		2			1	
1	33		31	4	29	2
	6		1	5		
4	33	3	31	6	37	6
		7			6	3

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5020 का हल

5	7	2	4	3	6	1
3	31	1	23	6	32	2
6	3	4	1	2	7	5
1	30	6	33	4	36	4
2	1	7	4	5	6	3
7	35	3	35	7	37	6
4	6	5	3	1	2	7

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

ओबीसी जातियों की पहचान

मोहन। गुजरात के उप–मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने अपने एक भाषण में बड़ी विचारोत्तेजक बहस छेड़ दी। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि भारत में हिंदुओं की बहुसंख्या नहीं होती तो क्या होता ? उन्होंने कहा कि यदि वैसा होता तो देश में न कोई धर्म–निरपेक्षता होती, न कानून का राज होता, न संविधान होता और न ही कोई मानव अधिकार होते। पटेल के इस कथत का आंतरिक अर्थ यह हुआ कि भारत हिंदू राष्ट्र है। इसीलिए यह वैसा है जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसी कथन का दूसरा पहलू यह है कि दुनिया के जिन राष्ट्रों में दूसरे मजहबियों का बहुमत है, वहां की शासन–व्यवस्थाओं में वे सभी खूबियाँ नदारद हैं, जो भारत में हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यूरोप और अमेरिका जैसे राष्ट्रों में हिंदू बहुसंख्या में नहीं हैं लेकिन उदारता के वहां वे सब लक्षण विद्यमान हैं, जो भारत में हैं। लेकिन पटेल का इशारा कुछ दूसरी तरफ है।